अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

26-29 नवंबर 2015, भुवनेश्वर (ओडिशा)

प्रस्ताव क्र. 1

"शिक्षा की समग्र एवं व्यापक नीति - समय की आवश्यकता"

देशभर में नई शिक्षा नीति पर व्यापक चर्चा-परिचर्चा होना एक सुखद अनुभव है। सामान्य विद्यार्थी से लेकर अध्यापकों व शिक्षाविदों तक सभी के द्वारा देश में शिक्षा जगत में जुड़ रहे इस नये अध्याय की रचना में अपना योगदान दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विषय में अभाविप का मानना है कि शिक्षा नीति को मात्र पाठ्यक्रमों या मूलभूत संरचना तक ही सिमित न मानकर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास व शिक्षा के प्रति योग्य वातावरण के निर्माण के रूप में देखा जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति में सभी विद्यार्थियों के विषय में विचार होना चाहिए तथा शिक्षा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। अभाविप शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की पक्षधर है।

अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए सरकारी संस्थाओं में सुधार आवश्यक है विशेषत: सभी नियामक संस्थाओं के कार्यों में एकरूपता लाई जानी चाहिए। कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से लेकर मानविकी विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय होना चाहिए। विद्यार्थी समाज-जीवन से जुड़े व सामाजिक संवेदना का बीज उनमें प्रस्फुटित हो ऐसे प्रयास होने चाहिए। जमीन, समाज व संस्कृति के प्रति उनमें संवेदना उकेरना भी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा को एक पास-फेल सिस्टम से ऊपर उठाकर व्यक्तित्व के समग्र विकास का वाहक बनाने का प्रयास होना चाहिए।

सस्ती, गुणवत्तापूर्ण व सर्वसुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अभाविप का यह 61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन देश में लगातार बढ़ते शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून की अपनी मांग दोहराता है। साथ ही, शिक्षा क्षेत्र के हित में केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। वर्तमान समय में, निजी शिक्षा के महत्व व भूमिका को समझते हुए सुशासन की नीति का इन संस्थानों में भी प्रसार होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मात्र अभियान न चलाकर उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखकर एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है। अभाविप प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराने की माँग करती है।

जाति, लिंग, गरीबी और भौगोलिक आधार पर पिछड़े विद्यार्थियों को समान अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिए। साथ ही, भारतीय मेधाओं व प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें उचित स्तर पर सम्मान व छात्रवृत्ति द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। विकलांग एवं अशक्त विद्यार्थियों हेतु शिक्षण संस्थाओं में विशेष व्यवस्था हो हालांकि महानगरों में इस प्रकार की व्यवस्था सीमित रूप में ही सही उपलब्ध है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र इस व्यवस्था से पूर्णत: वंचित है। उन्हें भी संसाधन प्रदान कर उनके सम्यक शिक्षा की व्यवस्था हो।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही भारतीय शिक्षा को भारतीय मूल्यों के अनुरूप संचालित करने की मांग करती रही है। नई शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत का गौरवशाली इतिहास सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, वर्तमान सरकार द्वारा महापुरुषों पर कुछ डाक-टिकट जारी किए गए है। अभाविप इस पहल का स्वागत करती है और यह मांग करती है कि शेष के महापुरुषों के व्यक्तित्व व कृतित्व को

पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अभाविप का यह सुविचारित मत है कि नालंदा व तक्षशिला की भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर वर्तमान में विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के अच्छे पाठ्यक्रमों से प्रेरणा लेकर देश के युवाओं में आत्मगौरव व सर्वआयामी ज्ञान का संचार हो, इस शिक्षा में प्रयास होना चाहिए। संविधान के दायरे में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को सभी धर्मों की सही जानकारी मिल सके।

अभाविप का मत है कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। सरकारी शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जाए व सभी स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति सुनिश्चित की जाये शिक्षा सेवा चयन में पारदर्शिता लाने हेतु एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हो। यह राष्ट्रीय कर्तव्य है वो शिक्षा क्षेत्र हेतु पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करे। अभाविप का यह 61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार से पुन: यह पुरजोर मांग करता है कि बजट का दसवां हिस्सा या GDP का 6 फीसदी भाग शिक्षा पर खर्च किया जाए।

अभाविप देशभर के शिक्षार्थी, शिक्षक व शिक्षाविदों का आह्वान करती है कि वे अपने सुझावों के माध्यम से एक समग्र शिक्षा नीति हेतु ठोस पहल करें। अभाविप देशभर से प्राप्त सुझावों व चर्चा के पश्चात् एक प्रस्ताव शीघ्र ही सरकार को सौंपेगी। अभाविप सरकार से माँग करती है कि पूर्व नीतियों के व्यावहारिक अनुभवों से सीख लेते हुए नई शिक्षा नीति को सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कर शिक्षा–जगत व जनमानस की अपेक्षाओं को पूरा करे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

26-29 नवंबर 2015, भुवनेश्वर (ओडिशा)

प्रस्ताव क्र. 2

"आतंकवाद व छद्म धर्मनिरपेक्षता के भारत विरोधी गठजोड़ के खिलाफ एकजुट हो देश"

फ्रांस के पेरिस और माली के बामाको में विगत दिनों हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को पुन: हिलाकर रख दिया है और दूनिया के कुछ देशों ने आतंक का पर्याय एक महजब को ही मानते हुए उसके विरूद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है। अलकायदा के बाद आई.एस.आई.एस. ने विश्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। विश्व के अनेक देशों के साथ भारत तो आतंकवाद का सर्वाधिक शिकार रहा है। आई.एस.आई.एस. जैसे आतंकी संगठन से भारत के एक वर्ग विशेष के कुछ युवाओं का संपर्क में रहना चिंता का विषय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिंसा एवं आतंकवाद विरोधी सारी शक्तियाँ अपने सभी मतभेद भूलकर भारत समेत दुनिया में चल रहे आतंक के विरुद्ध एकजुट हों ओर इस आतंकवाद रूपी दानव का समूल विनाश करें। एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी तरफ ऐसी विकट परिस्थिति में भारत के छद्म सेकुलर बुद्धिजीवी व अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आकण्ठ डूबे राजनेता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश की सुरक्षा एवं अखण्डता को अस्थिर करने का षड्यंत्र करते हुए भारत में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी एवं अलगाववादी समूहों का संरक्षण करते दिख रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड घोषित आतंकवादियों अफजल गुरू, अजमल कसाब, याकूब की फाँसी पर छाती पीटना, आतंकी घटनाओं को प्रतिक्रियाजन्य बताना, बिहार चुनाव से पूर्व आकस्मिक घटना को आधार बनाकर देश में असहिष्णुता का ढोंग करना, विदेशी संस्थाओं के द्वारा पोषित तथाकथित बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार लौटाना, कांग्रेस नेताओं द्वारा पाक में भारत विरोधी बयान देना कर्नाटक में राज्य सरकार द्वारा टीपू सुल्तान की जयंति मनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, केरल में पॉपूलर फ्रंट की सांप्रदायिक गतिविधियाँ इत्यादि। यह स्पष्ट करता है कि देश में एक ऐसा नापाक गठजोड़ बन गया है जो भारत की अहिष्णुता की वैश्विक पहचान के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अ.भा.वि.प. का यह 61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे तत्वों की ओछी व घिनौनी हरकत की कठोर शब्दों में भर्त्सना करता है।

विगत लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी ताकतों की विजय के साथ ही वैश्विक क्षितिज पर भारत के उभार से बौखलाए राष्ट्रविरोधी गठजोड़ द्वारा अचनाक देश में असहिष्णुता का राग अलापना अत्यंत निंदनीय है। शासकीय एवं विदेशी संस्थाओं (फोर्ड फाउन्डेशन, ग्रीन पीस जैसी संस्थाओं) के धन पर केन्द्र सरकार द्वारा रोक लगा देने से उस धन पर पोषित छद्म सेकुलर बुद्धिजीवी और तथाकथित साहित्यकार अचानाक बौखला उठे हैं। उन्हें देश में लगे आपातकाल के समय लोकतंत्र का गला घोंटने, अपने ही देश में शरणार्थी बनने को विवश किये गये 3 लाख कश्मीरी हिन्दुओं के नरकीय जीवन, 1984 में 3000 से अधिक सिक्खों की हत्याओं, सिंगुर, नंदीग्राम की पाशविक घटनाओं, पश्चिम बंगाल व केरल में कम्युनिस्ट शसन के दौरान विरोधी विचारों के कार्यकर्ताओं पर ढाए गए जुल्म व उनकी बर्बर हत्याओं जैसी अनेक घटनाओं पर असहिष्णुता क्यों नहीं दिखाई पड़ी? बिहार चुनाव से ठीक पहले देश में बढ़ रही असहिष्णुता के नाम पर मचाए जाने वाला शोर अचानक चुनाव परिणाम आते ही थम सा क्यों गया? इससे यह ज्ञात होता है कि इन सबके पीछे निश्चित ही कोई न कोई षड्यंत्र है।

वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रविरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के ये सिपहसालार भारत में अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। ये राष्ट्रविरोधी तत्व इतने उच्छृंखल हो चुके हैं कि निर्दोष नागरिकों के हत्यारों, राष्ट्रघाती आतंकवादियों के लिए आधी रात को मा.सर्वोच्च न्यायालय को खोलने के लिए मजबूर करते हैं, पाकिस्तान में जाकर भारतीय सम्प्रभुता विरोधी बयान देते हैं और इन आतंककियों के समर्थन में अत्यंत घृणित तरीके से एक स्वर में चिल्लाने लगते है। Save Dog-Save Tiger पशु प्रेम व मानवता की पहचान है परंतु Save Cow पर सांप्रदायिकता का शोर मचाना व कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहना, यह कौन–सी मानसिकता है ? इस प्रकार की विकृत मानसिकता व सोच वाले तथाकथित प्रगतिशील लोग कहीं न कहीं लगातार राष्ट्रवाद को चुनौती देने का प्रयास कर रहे है।

अ.भा.वि.प. का यह 61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन देश के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों–साहित्यकारों, युवाओं व छात्र–छात्राओं से आवाहन करता है कि वे इस अपवित्र गठजोड़ को समझते हुए इसके विरूद्ध एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लें। साथ ही देश की छात्र–युवा शक्ति से अपेक्षा करता है कि वह सभी महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों से लेकर समाज में वैचारिक बहस प्रारंभ करे और राष्ट्रविरोधी गठजोड़ को परास्त कर राष्ट्रवादी विचार को स्थापित करे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

26-29 नवंबर 2015, भुवनेश्वर (ओडिशा)

प्रस्ताव क्र. 3

पूर्वोत्तर के विकास में छात्र-युवा नेताओं की भूमिका

पूर्वोत्तर विविधता, बहु-संस्कृति व खनिज संपदा के साथ ही प्राकृतिक सुन्दरता का अनुपम क्षेत्र है। अभाविप ने सदैव इस क्षेत्र के विकास, सुरक्षा तथा यहाँ की विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास किया है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूर्वोत्तर के विस्तृत अध्ययन के आधार पर, भारत के शेष राज्यों से सीधा संवाद, छात्र-छात्राओं के द्वारा हो-इसके लिए अनुठा उपक्रम SEIL 1966 में प्रारंभ किया। आज SEIL अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस प्रकल्प के माध्यम से पूर्वोत्तर की भौगोलिक जानकारी, आतंकी संगठनों का प्रभाव, विकास, शिक्षा में पिछड़ता पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को देश व पूर्वोत्तर के समक्ष गंभीरता से रखने का प्रयास किया है। अभाविप का यह सुविचारित मत है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना सम्पूर्ण भारत का विकास संभव नहीं है और पूर्वोत्तर के विकास में उस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित हो।

अभाविप ने SEIL के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर SEIL के अनुभव के आधार पर पूर्वोत्तर के छात्र / युवा संगठनों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। दिल्ली में 3 अक्टूबर को आयोजित पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद में भाग लेने वाले सभी छात्र-युवा संगठनों के प्रतिनिधियों का अभाविप का यह 61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन 2015 अभिनन्दन व स्वागत करता है।

इन प्रतिनिधियों द्वारा न केवल पूर्वोत्तर के विकास अपितु भारत के विकास और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए संकल्प लेना ऐतिहासिक स्वागत योग्य प्रयास है। इस छात्रनेता-युवा संसद में जिस प्रतिबद्धता व जिम्मेदारी के साथ सभी ने न्यूनतम साझा संकल्प दोहराया, इस संकल्प से पूर्वोत्तर के विकास हेतु पोषक वातावरण निर्माण होगा ऐसा विश्वास सभी छात्र नेताओं ने जताया, विद्यार्थी परिषद इसको बड़ी उपलब्धि मानती है।

- राष्ट्रीय एकता, अखंडता और पूर्वोत्तर में समुचित विकास के लिए अनुकूल माहौल बने इस हेतु अभाविप हमेशा प्रतिबद्ध होकर आगे भी सक्रियता से कार्य करती रहेगी।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में सहयोग करना हमारी प्राथमिकता होगी।
- सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और पूर्वोत्तर के विकास हेतु सामूहिक प्रयास
- नशा-मुक्त पूर्वोत्तर
- भ्रष्टाचार-मुक्त पूर्वोत्तर
- हिंसा-मुक्त पूर्वोत्तर
- युवा शक्ति का विकास-ध्येय में रखकर सतत् सामूहिक प्रयासों का आग्रह हो।

- भारत के अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहें पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए देशभर में भयमुक्त और संरक्षित माहौल का निर्माण हो।
- पूर्वोत्तर में शान्तिपूर्ण तथा जीवन यापन हेतु अनुकूल माहौल निर्माण करना यह सबका सामूहिक प्रयास बने।

अभाविप का 61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार व पूर्वोत्तर की सभी राज्य सरकारों से मांग करता है कि पूर्वोत्तर के समग्र विकास की व्यापक नीति बनाकर देश के विकास में पूर्वोत्तर की भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अभाविप देश के नागरिकों, छात्र–युवाओं से आहवान करती है कि SEIL द्वारा चलाये जा रहे "पूर्वोत्तर को जानो – भारत को जानो", अभियान में सहभागी हो तथा वहाँ की समस्याओं को समझकर उनके समाधान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अभाविप पूर्वोत्तर के छात्रों–युवाओं से आहवान करती है कि वे देश विरोधी ताकतों के विघटनकारी मंसूबों को पहचानकर उनके विरुद्ध एकजुट होकर उनका प्रतिकार करें और पूर्वोत्तर में SEIL द्वारा चलाई जा रही विभिन्न रचनात्मक व विकासात्मक गतिविधियों में अपनी सहभागिता प्रदान करे, जिससे की पूर्वोत्तर क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

26-29 नवंबर 2015, भुवनेश्वर (ओडिशा)

प्रस्ताव क्र. 4

पर्यावरण संरक्षण कर प्रभावी नेतृत्व करे भारत

मानव और पर्यावरण का परस्पर अन्त: सम्बन्ध रहा है परंतु 18 वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ से मानव ने प्रकृति का शोषण कर पर्यावरण को उसके अनुकूलन क्षमता से कहीं अधिक प्रभावित किया है। जिसका दुष्परिणाम हर प्राणीमात्र पर होने वाला है। विश्व में इस औद्योगिक क्रांति के पुरोधा विकसित देशों ने पूँजीवाद पर आधारित उपभोगवादी वृति का प्रचार किया, जिससे आज वैश्विक पटल पर पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे केंद्रीय विषय बने है।

आईपीसीसी (Intergovernmental Panel on Climate Change) की 2007 की रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 1970 से 2004 के मध्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्ज 70% बढ़ा है। वर्ष 2011 की ओईसीडी (Organization for Economic Co-operation & Development) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में ओईसीडी विकसित देशों ने औसतन 10 टन CO_2 प्रतिव्यक्ति उत्सर्जित किया जब कि उसी वर्ष में भारत ने लगभग 1.5 टन प्रतिव्यक्ति उत्सर्जित किया।

आगामी 30 नवम्बर 2015 से पेरिस में प्रारंभ हो रहे 'संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन अधिवेशन' में विकसित राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन पर कमी लाने हेतु नियम गढ़ने जा रहे है, जिसमें गरीब, कमजोर एवं विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाना विकसित राष्ट्रों की कुटिल नीति है। विकसित राष्ट्र अपना कार्बन एवं अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए तैयार नहीं है तथा अविकसित व विकासशील देशों पर उचित स्तर तक कार्बन उत्सर्जन न करने का दबाव बनाकर उनको पिछड़ा ही रहने देना चाहते है ताकि अविकसित व विकासशील देशों में उनके उत्पादों के उपभोग विश्वभर में सुनिश्चित रहें। विकसित देशों को इसी दोहरे मापदंड की नीति से समाधान का मार्ग अत्यंत जटिल एवं दीर्घकालीन हो रहा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 61 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन भारत सरकार से आवाहन करता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के इस जलवायु परिवर्तन अधिवेशन में विकासशील एवं कमजोर देशों के हितों की रक्षा करते हुए सक्षम नेतृत्व दे। जहाँ एक ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचासा पर औद्योगिक देशों की हठवादिता जिसमें वे अपने अति-भोगवाद के जीवनस्तर को नियंत्रित नहीं करना चाहते, वहीं दूसरी ओर अन्य देशों में जीवनस्तर सुधार सके, इसके लिए ग्रीन तकनीकि देना भी नागवार गुजर रहा है। जिसके लिए वे बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे नियमों की दुहाई देकर इन तकनीकों पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते है, साथ ही विकासशील देशों को वे अपने पुराने उत्पादों का डम्पिंग ग्राउंड बनाते है। और कार्बन ट्रेंडिंग जैसे माध्यमों से अपना प्रदूषण जारी रखते है।

अभाविप मानती है कि भारत को समय-समय पर विकासशील राष्ट्रों के हित के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण, जैवविविधता सम्पन्न तथा नैसर्गिक जीवन के प्रति श्रद्धा रखने वाली जीवन पद्धति के साथ विकास करने वाले राष्ट्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और विश्वमंचो पर उनकी सराहना सुनिश्चित करनी चाहिए।

विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि भारत प्राचीन परम्पराओं के अनुसार कम प्रदूषण तथा अनुकूलन की क्षमता को विकसित करके, विकास का उपयुक्त मॉडल विश्व को प्रस्तुत करें तथा अंतरराष्ट्रीय दबाव से अलग जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मापदण्ड करें।

अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन देश के विद्यार्थियों तथा छात्रसंघों से अपील करता है कि वे परिसरों में पर्यावरण संरक्षण की सकारात्मक बहस खड़ी करें तथा समाज को सार्वजनिक यातायात साधनों के प्रयोग एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागृत करें।